MR. CHAIRMAN : Ask only question.

श्रीमती रूपा गांगुली: महोदय, प्रश्न रिक्वेस्ट के फॉर्म में है कि पश्चिम बंगाल में केन्द्र सरकार के इतने काम होने के बावजूद एडवर्टाइज़मेंट बंगला में क्यों नहीं आता? मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सरकार इस पर ज्यादा गौर करे। पैसा खर्च होता है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं दिखता है, क्या होता है?

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर: सभापति जी, मैं माननीय सांसद की भावना को समझता हूं और मैं उनको वास्तविकता बताना चाहूंगा कि दो तरह के विज्ञापन, एक मंत्रालय के खुद के साधनों से और दूसरा क्लाइंट मिनिस्ट्रीज़ के साधनों से जाते हैं। वर्ष 2017-18 के अंदर बंगाली अखबारों के अंदर जो विज्ञापन गए हैं, वे मंत्रालय से 2.2 करोड़ रुपये के दिए गए हैं और क्लांइट मिनिस्ट्रीज़ से 17.95 करोड़ रुपये के दिए गए हैं।

खुले में शौच-मुक्त घोषित किए गए गांव

*53. **श्रीमती छाया वर्मा**: क्या **पेयजल और स्वच्छता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अक्तूबर, 2014 के दौरान खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में यह संख्या कितनी है;

(ख) कितने जनपदों एवं गांवों को अब तक खुले में शौच-मुक्त घोषित किया जा चुका है;

(ग) खुले में शौच-मुक्त घोषित किए गए गांवों एवं जनपदों की वास्तविक स्थिति क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि खुले में शौच-मुक्त घोषित किए गए कई गांव और स्थान सच्चाई से परे हैं और उन्हें मात्र कागजों पर ही 'खुले में शौच-मुक्त' होना दर्शाया गया है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2012-13 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा करवाए गए आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार, अनुमान था कि दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 तक लगभग 9.85 करोड़ परिवार खुले में शौच करते थे और दिनांक 20 जुलाई, 2018 की स्थिति तक अनुमान है कि लगभग 1.93 करोड़ परिवार खुले में शौच करते हैं।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए आकड़ों के अनुसार, दिनांक 20.7.2018 की स्थिति तक देश में 417 जिले और 3,99,850 गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) एसबीएम (जी) दिशा-निर्देशों के अनुसार, गांवों और जिलों को जिलों तथा राज्यों द्वारा स्व-घोषणा की दृढ़ प्रक्रिया के माध्यम से और फिर बहु-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया द्वारा ओडीएफ घोषित किया जाता है। इसके अलावा, एसबीएम (जी) की विश्व बैंक सहायता

परियोजना के तहत एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी के माध्यम से हाल ही में किए गए राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) 2018 के अनुसार, 95.6% ओडीएफ सत्यापित गांवों के ओडीएफ होने की पुष्टि की गई।

Villages declared as Open Defecation Free

†*53. SHRIMATI CHHAYA VERMA: Will the Minister of DRINKING WATER AND SANITATION be pleased to state:

(a) the number of persons defecating in the open during October, 2014 and the number of the same at present;

(b) the number of districts and villages which have been declared as Open Defecation Free;

(c) the real status of villages and districts that have been declared as Open Defecation Free; and

(d) whether it is a fact that many villages and places which have been declared as Open Defecation Free have been entered only on papers and are far from reality?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI RAMESH CHANDAPPA JIGAJINAGI): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) As per the Baseline Survey conducted by the States/UTs in 2012-13, about 9.85 crore households were estimated to be defecating in open as on 2nd October, 2014. And, as on 20th July, 2018, about 1.93 crore households are estimated to be defecating in the open.

(b) As per the data reported by the States/UTs on the Integrated Management Information System (IMIS) of Swachh Bharat Mission(Gramin) [SBM(G)], 417 districts and 3,99,850 villages in the country have been declared as Open Defecation Free (ODF) as on 20.7.2018.

(c) and (d) As per guidelines of SBM(G), villages and districts are declared ODF through a rigorous process of self-declaration, followed by multi-level verification process by the districts and states. Further, as per recent National Annual Rural Sanitation Survey (NARSS) 2018, conducted by an independent verification agency under the World Bank support project to SBM-G, 95.6% of ODF verified villages were confirmed to be ODF.

† Original notice of the question was received in Hindi.

श्रीमती छाया वर्मा: महोदय, मैं समयाभाव के कारण अपने दोनों प्रश्न एक साथ करना चाहती हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: दोनों के लिए समाधान सभापटल पर रखा है। ये ऐसा बता रहे हैं।

श्रीमती छाया वर्मा: महोदय, आंकड़ों में गांवों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि दिल्ली भी खुले में शौचमुक्त नहीं हुई है। ...**(व्यवधान)**... ट्रेन से आते समय दिल्ली में घुसते ही ट्रेनों की पटरियां शौचयुक्त दिखने लगती हैं। मेरा प्रश्न है कि गरीब परिवार को गांव में शौचालय बनवाने के लिए मात्र 12 हज़ार रुपये स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिये जाते हैं और छत्तीसगढ़ में यह राशि दो किस्तों में देते हैं। पहली बार 6 हज़ार रुपये देते हैं और बाद में फिर 6 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन होता यह है कि पहली बार तो 6 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन दूसरी बार जो 6 हज़ार रुपये की राशि मिलती है, उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... उस राशि की बंदरबांट हो रही है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्रालय छत्तीसगढ़ राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालय में हो रही बंदरबांट को रोकने के लिए उचित कदम उठाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देगा और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराएगा?

श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी: महोदय, यह राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। मेंबर साहिबा बोल रही हैं कि करप्शन हो रहा हैं। अगर करप्शन होता है, तो हम डिटेल्ड इन्क्वायरी करते हैं।

श्रीमती छाया वर्मा: महोदय, क्या आप राज्य सरकार को जांच कराने के लिए निर्देश देंगे?

श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी: सर, हम राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए नहीं आते हैं, यह उनका सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग इन्क्वायरी करते हैं।

श्री रेवती रमन सिंह: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि शौचालय बनाने के लिए मात्र 12 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। 12 हज़ार रुपये में कोई शौचालय नहीं बन पाता है। वह नहीं बन पाने के कारण ज्यादातर गांवों में जो शौचालय बने हैं, वे शौचालय के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें लोग स्टोरेज के रूप में सामान रखते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे उसकी राशि बढ़ाने का काम करेंगे?

श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी: ऐसा कुछ विचार नहीं है। वह नहीं बढ़ा सकते।

श्री सभापति: वे कह रहे हैं कि ऐसा प्रस्ताव नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: महोदय, वह 12 हज़ार रुपये में नहीं बन पाएगा। उसको बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये कर दीजिए।

श्री राजमणि पटेलः महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन गांवों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया है उसके लिए सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया है और उसको पुरस्कार भी दिया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें 50 फीसदी से अधिक गलत आंकड़े दिए गए हैं। ...**(व्यवधान)**... क्या माननीय मंत्री महोदय समिति के माध्यम से इसकी जांच कराएंगे और इस संबंध में कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी: सभापति महोदय, देश में टोटल 417 जिले ओडीएफ घोषित किए गए हैं। **...(व्यवधान)...** Around 4,00,000 villages in the country ...(*Interruptions*)... और 417 जिले ओडीएफ डिक्लेयर किए गए हैं।

श्री अशोक बाजपेयी: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश को ओडीएफ मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है और कब तक पूरे प्रदेश को खुले शौचालय से मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी? **...(व्यवधान)...** इसे कब तक पूरा कर किया जाएगा?

श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी: महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है, वह मैं उन्हें उपलब्ध करा दूंगा।

Impact of climate change

*54. SHRI P. BHATTACHARYA: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether Government has conducted any study to assess the impact of climate changes in different fields including agriculture in India;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any action plan has been formulated by Government to combat ill effects of climate changes in coordination with the global agencies; and

(d) if so, the features of such action plan?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Government commissioned a scientific study to assess the impact of climate change and published its report titled "Climate Change and India: 4X4 Assessment - A Sectoral and Regional Analysis for 2030s". The report has assessed impact of climate change on four key sectors of Indian economy, namely Agriculture, Water, Natural Ecosystems and Biodiversity and Health in four climate sensitive regions of India, namely the Himalayan region, the Western Ghats, the Coastal Area and the North-East Region.

The study projects a mixed picture for climate parameters and related impact on the relevant sectors. The study projects a variable rate of agricultural production including decrease in yield in some crops and change in the composition of the forests